



Neutral Citation No.2026:AHC:2558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-44658 वर्ष 2025

श्री निवास आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अशोक कुमार सिंह बैस

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, लाल प्रभाकर सिंह

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह बैस, श्री चंद्रजीत सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री लाल प्रभाकर सिंह के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक अपराध संख्या-296 वर्ष 2025 में धारा 103(1), 191(2), 352, 351(2), 115(2) और 3(5) बी.एन.एस., थाना-जुनावाड़ी, जिला: संभल के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग उन्नीस दिनों की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सूचनाकर्ता द्वारा उसके बेटे भुवनेश द्वारा कहानी सुनाए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में प्राथमिकी में आवेदक की भूमिका को अलग किया गया है, हालांकि शुरुआत में, सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप थे। इसके बाद, स्टार गवाह भुवनेश का बयान दर्ज किया गया और उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं, इस तरह, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है।
6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 20.8.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी में देरी को ध्यान में रखते हुए और यह कि सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

9. आवेदक- श्री निवास, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 7, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)